

वाम ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और अन्य

बनाम

उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य

21 जनवरी, 1997

[ए.एम. अहमदी सी.जे. और एस.सी. सेन, जे.]

यू.पी. आबकारी अधिनियम 1910-धारा 41 नियम 2 उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1956 की धारा 2 और 18-जी के साथ पढ़े:- औद्योगिक शराब स्प्रिट का विकृतीकरण -अधिसूचना संख्या 25/लाइसेंस/3 दिनांक 18-5-1990, विकृतीकरण शुल्क लगाने के संबंध में- राज्य की विधायी क्षमता-अभिनिर्धारित, जब तक किसी भी मादक तैयारी काे मानव उपभोग के लिए मोड़ा जा सकता है, तब तक राज्यों के पास कानून बनाने के साथ-साथ कर आदि लगाने की शक्ति होगी और स्प्रिट का विकृतीकरण न केवल राज्यों पर एक दायित्व है, बल्कि इसे लागू करना राज्यों की क्षमता के भीतर भी है- विकृतीकरण शुल्क नियामक शुल्क की प्रकृति में है जिसके लिए प्रतिपूर्ति आवश्यक नहीं है- अभिनिर्धारित, शुल्क की दर 7 पैसे प्रति लीटर है, तथ्यों पर- युक्तियुक्त- भारत का संविधान अनुच्छेद 246, 254, 248 और अनुसूची VII सूची-II प्रविष्टियाँ 8, 51, 6, 24, 66, सूची-I प्रविष्टियाँ 84, 52, सूची-III प्रविष्टि 33।

भारत का संविधान।

अनुच्छेद 110 (2), 99 (2)- विनियामक/अनुज्ञप्ति शुल्क प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क से भिन्न है- विनियामक शुल्क के लिए प्रतिपूर्ति आवश्यक नहीं है हालांकि अधिभार उचित होना चाहिए।

सूची-II की प्रविष्टियाँ 8 और 51, को सूची-I की प्रविष्टि 84 के साथ पढ़ें- राज्यों को मानव उपभोग के लिए नशीली शराब या मादक शराब पर कानून बनाने का विशेषाधिकार है।

अपीलकर्ताओं के पास अपने उत्पादों के लिए मुख्य कच्चे माल के रूप में औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण और उपयोग का लाइसेंस था। राज्य विधानमंडल ने अधिसूचना संख्या 25/लाइसेंस/भाग-3 दिनांक 18-05-1990 के तहत स्पिरिट के विकृतीकरण का लाइसेंस रखने वाली डिस्टिलरी पर 7 पैसे प्रति लीटर की दर से लाइसेंस शुल्क लगाया।

अपीलकर्ताओं ने उक्त अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की कि राज्य के पास औद्योगिक शराब के संबंध में कानून बनाने या उसके संबंध में कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है और लेवी प्रतिपूर्ति की भावना पर आधारित नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया और रिट याचिकाएं खारिज कर दी। इस तरह, ये अपीलेें विशेष अनुमति के माध्यम से

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि जैसा कि इस अदालत ने सिंथेटिक और केमिकल्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जेटी 1989 (4) एससी 267 में कहा था कि संशोधित स्प्रिट औद्योगिक अल्कोहल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं, राज्य विधानमण्डल के पास इस संबंध में कानून बनाने या लाइसेंस शुल्क वसूलने या कोई अन्य शुल्क लगाने की शक्ति नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया कि उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1956 की धारा 2 में की गई घोषणा और अधिनियम की अनुसूची में मद 26 को जोड़ने के कारण औद्योगिक अल्कोहल संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में है और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 8 या 51 अधिसूचना का समर्थन नहीं कर सकती है। सूची-III की प्रविष्टि 33 भी इसे कायम नहीं रख सकी, क्योंकि यह क्षेत्र आई.डी.आर. अधिनियम की धारा 18-जी के प्रावधानों द्वारा व्याप्त था।

अपील को खारिज करते हुए इस न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1.1. हालाँकि, रेक्टिफाइड स्प्रिट विषैला होता है और मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त होता है, लेकिन पानी से पतला करने पर इसे देशी शराब के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित रेक्टिफाइड स्प्रिट के इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए, इसे डिनेचुरेट्स मिलाकर विकृत करना आवश्यक है, जो

स्प्रिट को अरुचिकर और मतली पैदा करने वाला बनाता हैं। इसका उद्देश्य  
मानव

उपभोग के लिए गैर-पीने योग्य शराब के दुरुपयोग को रोकना है। सिंथेटिक केमिकल मामले के फैसले को ध्यान से पढ़ने पर इस न्यायालय ने औद्योगिक शराब से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों की गणना की है जिसमें राज्य इसके दुरुपयोग को रोकने सहित कानून बना सकता है। [407-सी-डी; 414-बी-सी; एच]

1.2. जहां तक धारा 18 जी आई.डी.आर. अधिनियम के तहत शक्ति का संबंध है, इसका उपयोग केवल तभी तक किया जा सकता है जब तक उप-धारा (1) द्वारा अनुमति दी जाती है, अर्थात् किसी भी अनुसूचित उद्योग से संबंधित किसी भी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के उचित मूल्य पर एक समान वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, इस सीमा तक राज्य विधानमंडल कोई कानून नहीं बना सकता है, लेकिन अन्य मामलों में राज्य विधानमंडल के लिए क्षेत्र अभी भी खुला है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई आक्षेपित अधिसूचना कि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेक्टिफाइड स्पिरिट को देशी शराब या पीने योग्य शराब के अन्य रूप प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा गया था, प्रविष्टि 6 सूची-II- सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रविष्टि 8 सूची-II- के तहत उचित थी- नशीली शराब का कब्जा और बिक्री। [412-ए-बी]

1.3. सूची-I की प्रविष्टि 84 के साथ पठित सूची-II की प्रविष्टि 8 और 51 के तहत राज्य को मानव उपभोग के लिए नशीली शराब या

अल्कोहलिक शराब पर कानून बनाने का विशेषाधिकार है। इसलिए, जब तक कोई भी शराबी तैयारी को मानव उपभोग की ओर मोड़ा जा सकता है, राज्य के पास कानून बनाने के साथ-साथ कर लगाने की भी शक्ति होगी आदि.. इस दृष्टिकोण से स्पिरिट का विकृतीकरण न केवल राज्य पर एक दायित्व है, बल्कि इसे लागू करना राज्यों की क्षमता के भीतर भी है।

[415-ए-बी]

श्री बिलेश्वर खंड उद्योग खेडुत सहकारी मंडली लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य, [1992] 1 एससीसी 42: [1992] 1 एस.सी.आर. 391; गुजकेम डिस्टिलर्स इंडिया लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य, [1992] 1 एससीसी 339: [1992] 1 एस.सी.आर. 675 और आंध्रप्रदेश राज्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड, [1996] 3 एससीसी 709: जे. टी. (1996) 3 एस. सी. 679 पर भरोसा किया गया।

सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1990] (1) एस.सी. सी. 109:[1989] सप्लिमेंट 1 एस.सी.आर. 623 चर्चा और व्याख्या।

2. लाइसेंस के लिए ली जाने वाली फीस यानी नियामक शुल्क और प्रतिपूर्ति शुल्क के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के शुल्क के बीच का अंतर है। विनियामक शुल्क के मामले में, लाइसेंस शुल्क की तरह, प्रतिपूर्ति का अस्तित्व आवश्यक नहीं है, हालांकि लगाया गया शुल्क, मामले की

परिस्थितियों में, अत्यधिक नहीं होना चाहिए। विकृतीकरण की प्रक्रिया की निगरानी में शामिल कार्य की मात्रा और प्रकृति और राज्य द्वारा किए गए परिणामी खर्चों को ध्यान में रखते हुए 7 पैसे प्रति लीटर का शुल्क युक्तियुक्त और उचित था। [418-सी-डी; एच; 419-ए-बी]

कोर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता बनाम लिबर्टी सिनेमा, एआईआर (1965)  
एससी 1107: [1965] 2 एस. सी. आर. 447, संदर्भित।

जॉर्ज वाल्केम शैनन बनाम लोअर मेनलैंड डेयरी उत्पाद बोर्ड, 1938  
एसी 708: ए.आई.आर. (1939) पी. सी. 36, संदर्भित।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 230/1997  
आदि।

सी.एम.डब्ल्यू.पी. संख्या 16782, 1990 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय  
के निर्णय दिनांक 9.9.9 से

डी. ए. दवे, सुश्री माणिक करंजावाला, भास्कर प्रधान और पी. के.,  
अपीलकर्ताओं की ओर से मलिक।

एम. के. बनर्जी, भारत के अटॉर्नी जनरल, आर. बी. मिश्रा और  
सुश्री नलिन त्रिपाठी उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

## अहमदी, सी.जे. अनुमति दी गई।

ये दोनों अपीलें उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिनांक 9.9.1991 के फैसले के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा आबकारी आयुक्त, उत्तरप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 25/लाइसेंस/भाग-3 दिनांक 18.5.1990 को चुनौती देते हुए दायर की गई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। दिनांक 18.5.1990 की आक्षेपित अधिसूचना उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1990 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना द्वारा अधिसूचना संख्या 423-पांच/284/बी, दिनांक 26 सितंबर 1990 के साथ प्रकाशित नियमों में कुछ संशोधन किए गए थे। अधिनियम की धारा 41, नियम बनाने के लिए अन्य रूप से किसी भी नशीले पदार्थ का निर्माण, आपूर्ति, भंडारण या बिक्री; किसी भी नशीले पदार्थ को जमा करने और हटाने को विनियमित करने और उक्त अधिनियम की धारा 24 और 24 ए के तहत किसी विशेष या अन्य विशेषाधिकार के अनुदान सहित लाइसेंस, परमिट या पास के लिए देय शुल्क के पैमाने या शुल्क तय करने के तरीके को निर्धारित करने के लिए आबकारी आयुक्त को शक्ति प्रदान करती है। पहले वाले नियम 2 को "स्पिट का विकृतीकरण" नामक एक नए नियम 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। संशोधित नियम में स्पिट के विकृतीकरण के



लिए निर्धारित प्रपत्र में एक नया लाइसेंस कलेक्टर द्वारा अपने जिले के भीतर स्थित सभी डिस्टिलरीज जिनके पास लाइसेंस पीडी-1 या पीडी-2 है और जिनके पास लाइसेंस एफएल-16, एफएल-39, एफएल-40 और एफएल-41 है, को जारी करने का प्रावधान है। इसमें आगे निर्धारित किया गया है कि ऊपर उल्लिखित डिस्टिलरीज और जिनके पास स्पिरिट के विकृतीकरण का लाइसेंस है, उन्हें 7 पैसे प्रति लीटर की दर से अग्रिम रूप से विकृतीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। अपीलकर्ता वैम ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड विनाइल एसीटेट मोनोमर का निर्माण कर रहे हैं, जो एक बुनियादी कार्बनिक रसायन है जिसके लिए औद्योगिक अल्कोहल मुख्य फीड स्टॉक है। अपीलकर्ताओं की डिस्टिलरी में औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन किया जा रहा है और अपीलकर्ताओं के अनुसार उत्पादित पूरी औद्योगिक अल्कोहल राज्य आबकारी अधिकारियों द्वारा अनुमोदित विधि के अनुसार विकृत है और विनाइल एसीटेट मोनोमर के निर्माण के लिए उनके कारखाने में उपयोग किया जा रहा है। अन्य अपीलकर्ता, अर्थात्, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड और अन्य, मोनोएथिलीन ग्लाइकोल और इसके उत्पादों डायथिलीन ग्लाइकोल और हेवी ग्लाइकोल का निर्माण कर रहे हैं। इन अपीलकर्ताओं की फ़ैक्टरी के एक हिस्से का उपयोग उनके द्वारा उत्पादित एथिल अल्कोहल के निर्माण के लिए किया जा रहा है, जिसे कैप्टिव रूप से उपभोग किया जा सकता है।

अपीलकर्ताओं के पास FL-39 के रूप में लाइसेंस है ताकि वे अपने उत्पाद के लिए मुख्य कच्चे माल के रूप में औद्योगिक अल्कोहल का उपयोग कर सकें। वे विवादित अधिसूचना में निर्धारित डीएस-1 के रूप में लाइसेंस लेने और 2 जून, 1990 से 7 पैसे प्रति लीटर की दर से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य थे। अधिसूचना को दो आधारों पर चुनौती दी गई है, अर्थात्, कि उत्तर प्रदेश राज्य के पास औद्योगिक अल्कोहल के संबंध में कानून बनाने या उसके संबंध में कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है और इसके अलावा यह लेवी प्रतिपूर्ति पर आधारित नहीं होने के कारण अन्यायपूर्ण थी। उत्तर प्रदेश राज्य ने रिट याचिकाओं का विरोध किया। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। अतः विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें।

आगे बढ़ने से पहले औद्योगिक अल्कोहल, डिनेचर्ड स्पिरिट और पीने योग्य शराब के बीच अंतर को समझना उचित होगा। एथिल अल्कोहल 95% v/v शक्ति का रेक्टिफाइड स्पिरिट है। रेक्टिफाइड स्पिरिट अत्यधिक विषैला होता है और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होता है। हालाँकि, पानी से पतला किया गया रेक्टिफाइड स्पिरिट देशी शराब है। रेक्टिफाइड स्पिरिट, जैसा कि यह है, उसका उपयोग विभिन्न अन्य उत्पादों जैसे रसायनों आदि के निर्माण के लिए किया जा सकता है। औद्योगिक उपयोग

के लिए उत्पादित रेक्टिफाइड स्प्रिट को अधिनियम के तहत जारी एक अधिसूचना के अनुसार विकृत किया जाना आवश्यक है ताकि स्प्रिट को मानव उपयोग के लिए निर्देशित होने से रोका जा सके। रेक्टिफाइड स्प्रिट को डिनाटुरेंट्स मिलाकर विकृत किया जाता है, जो स्प्रिट को अरुचिकर और मतली पैदा करने वाला बना देता है। इस प्रकार संशोधित स्प्रिट को पीने योग्य शराब में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन एक बार विकृत करने के बाद इसका उपयोग केवल औद्योगिक अल्कोहल के रूप में किया जा सकता है। उत्तरदाता द्वारा वर्णित विकृतीकरण की प्रक्रिया को उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया है:

"संशोधित स्प्रिट का विकृतीकरण एक उच्च तकनीकी प्रक्रिया है। प्रत्येक ड्रम/लॉट/बैच का परीक्षण मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आबकारी मुख्यालय प्रयोगशाला में किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अनुमति देने से पहले यह निर्धारित विनिर्देश के अनुसार संशोधित स्प्रिट को विकृत करने के लिए उपयोग में लेने की अनुमति देने से पहले वे निर्धारित विनिर्देश के अनुसार हैं। ठीक से परीक्षण किए जाने के बाद, विकृतीकरण को डिस्टीलटी के प्रभारी अधिकारी के ताले और

चाबी के नीचे अलग से संग्रहित किया जाना चाहिए, और विकृतीकरण के समय मापी गई मात्रा को विकृतीकरण वत्स में पंप किया जाता है। मिश्रण की प्रक्रिया कई घंटों तक चलती है। परिणामी मिश्रण डिनेचर्ड स्पिरिट या विशेष रूप से डिनेचर्ड स्पिरिट है, जैसा भी मामला हो। डिनेचर्ड करने के बाद, यह पता लगाने के लिए फिर से परीक्षण किया जाता है कि यह ठीक से डिनेचर्ड हुआ है या नहीं। आबकारी विभाग बाध्य है एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त के मुख्यालय में इस उद्देश्य के लिए प्रयोगशाला का रखरखाव किया जाता है। यहां एक मुख्य विकास अधिकारी होता है, जिसकी सहायता के लिए चार सहायक अल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट और उपकरण और अन्य उपकरणों के अलावा बड़ी संख्या में सहायक कर्मचारी होते हैं। उत्तरप्रदेश के आबकारी मैनुअल खण्ड 1 के नियम 785 के प्रावधानों के अनुसार विकृतीकरण आबकारी अधिकारियों की निगरानी में होता है।"

उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया पहला तर्क यह था कि रेक्टिफाइड स्पिरिट औद्योगिक अल्कोहल है जैसा कि सिंथेटिक एंड केमिकल्स

लिमिटेड बनाम यूपी राज्य (1990) 1 एससीसी 109 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होने के कारण, राज्य विधानमंडल के पास इसके संबंध में कानून बनाने या लाइसेंस शुल्क वसूलने या अन्य शुल्क लगाने की कोई शक्ति नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की अनुसूची में मद 26 व उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1956 (इसके बाद इसे "आईडीआर अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 2 में की गई घोषणा के आधार पर औद्योगिक अल्कोहल संसद के क्षेत्र में है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 8 या 51 विवादित अधिसूचना का समर्थन नहीं कर सकती। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि सूची III की प्रविष्टि 33 इसे कायम नहीं रख सकती क्योंकि यह क्षेत्र आईडीआर अधिनियम की धारा 18 जी के प्रावधानों द्वारा व्याप्त है।

जहां तक सूची II का संबंध है, आक्षेपित निर्णय प्रविष्टि 6, 8, 24, 51 और 66 को संदर्भित करता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अधिसूचना प्रविष्टि 6 और 8 द्वारा कवर की गई है। उक्त प्रविष्टियाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:-

"6. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय

8. नशीली शराब, यानी नशीली शराब का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री।

24. उद्योग सूची I की प्रविष्टि 7 और 52 के प्रावधान के अधीन।

51. राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादित समान वस्तुओं पर समान या निम्न दरों पर प्रतिकारी शुल्क:-

(ए) मानव उपभोग के लिए मादक शराब;

(बी) अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाएं  
और नशीले पदार्थ;

लेकिन इसमें अल्कोहल या इस प्रविष्टि के उप-पैराग्राफ  
(बी) में शामिल किसी भी पदार्थ से युक्त औषधीय और  
शौचालय की तैयारी शामिल नहीं है।

66. इस सूची में किसी भी मामले के संबंध में फीस,  
लेकिन किसी भी अदालत में ली गई फीस शामिल नहीं है।"

देशी शराब, आईएमएफएल, वाइन आदि का उत्पादन, कब्जा, भंडारण  
और वितरण पूरी तरह से राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। (धारा 24-बी, उ.प्र.

आबकारी अधिनियम देखें)। यू.पी. आबकारी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम रेक्टिफाइड स्पिरिट के उत्पादन के लिए लाइसेंसिंग देशी शराब आदि प्राप्त करना, साथ ही इन उत्पादों को रखने, भंडारण और व्यापार करने के लिए एक प्रणाली निर्धारित करते हैं। उच्च न्यायालय का कहना है कि लाइसेंसिंग का दोहरा उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और हानिकारक वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करना है। उच्च न्यायालय ने सूची-II की प्रविष्टियों 6 और 8 को स्पिरिट के विकृतीकरण के लिए कानून और परिणामी लाइसेंस प्रदान करने के रूप में और प्रविष्टि 51 को शुल्क लगाने की गुंजाइश प्रदान करने वाला पाया है।

सूची-III पर आते हुए, प्रासंगिक प्रविष्टि 33 है:

"33. व्यापार और वाणिज्य, और उत्पादन, आपूर्ति और वितरण,

(ए) किसी भी उद्योग के उत्पाद जहां संघ द्वारा ऐसे उद्योग का नियंत्रण संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित



में समीचीन घोषित किया जाता है, और ऐसे उत्पादों के समान आयातित सामान;

(बी) खाद्य पदार्थ, जिनमें खाद्यतिलहन और तेल शामिल हैं;

(सी) मवेशियों का चारा, जिसमें खली और अन्य सांद्र शामिल हैं

(घ) कच्चा कपास, चाहे वह कूटा हुआ हो या बिना कूटा हुआ, और कपास के बीज; और

(ई) कच्चा जूटा।"

एक समान प्रविष्टि 52 सूची-1 है:

"52. उद्योग, जिनका नियंत्रण संघ द्वारा संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया गया है।"

आईडीआर अधिनियम की धारा 2 द्वारा एक घोषणा की गई है कि

"सार्वजनिक हित में यह समीचीन है कि संघ को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।"

पहली अनुसूची के आइटम 26 में बताया है:

"26. किण्वन उद्योग

1. शराब

2. किण्वन उद्योगों के अन्य उत्पाद।

सूची-II की प्रविष्टि 24 को याद करें:

"24. उद्योग सूची I की [प्रविष्टियाँ 7 और 52] के प्रावधानों के अधीन हैं।"

आक्षेपित निर्णय अब यह जांचने के लिए आगे बढ़ता है कि आईडीआर अधिनियम द्वारा कितने क्षेत्र पर कब्जा किया गया है ताकि राज्य विधानमंडल के लिए उपलब्ध क्षेत्र का पता लगाया जा सके।

धारा 18 जी केंद्र सरकार को किसी भी अनुसूचित उद्योग से संबंधित किसी भी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग में आपूर्ति और वितरण और व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने का अधिकार देती है, जहां तक उचित वितरण और उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह

आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है। उप-धारा (2) उन विभिन्न प्रावधानों को निर्दिष्ट करती है जो उप-धारा (1) के तहत किए जा सकते हैं:

"18-जी. कुछ वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण, कीमत आदि को नियंत्रित करने की शक्ति।- (1) किसी भी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के न्यायसंगत वितरण और उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या समीचीन लगती है किसी भी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद इस अधिनियम में, अधिसूचित आदेश द्वारा, उसकी आपूर्ति और वितरण और उसके व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने का प्रावधान करती है।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके तहत बनाया गया एक अधिसूचित आदेश प्रदान कर सकता है-

(ए) उन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जिन पर ऐसी कोई वस्तु या उसका वर्ग खरीदा या बेचा जा सकता है;

(बी) लाइसेंस, परमिट, या अन्यथा, किसी भी ऐसी वस्तु या उसके वर्ग के वितरण, परिवहन निपटान, अधिग्रहण, कब्जे, उपयोग या उपभोग को विनियमित करने के लिए;

(सी) आम तौर पर बिक्री के लिए रखे गए किसी भी ऐसी वस्तु या उसके वर्ग की बिक्री पर रोक लगाने के लिए

(डी) ऐसी वस्तुओं या उसके वर्ग का उत्पादन करने वाले या स्टॉक में रखने वाले किसी भी व्यक्ति को एक

निर्दिष्ट अवधि के दौरान इस तरह से निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के पूरे या कुछ हिस्से को बेचने या इस तरह रखी गई वस्तुओं के पूरे या कुछ हिस्से को बेचने की आवश्यकता के लिए ऐसे व्यक्ति या वर्ग या व्यक्तियों को स्टॉक और ऐसी परिस्थितियों में जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(ई) ऐसी वस्तु या उसके वर्ग से संबंधित किसी भी वर्ग या वाणिज्यिक या वित्तीय लेनदेन को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए जो आदेश देने वाले प्राधिकारी की राय में हैं, या यदि अनियमित हैं तो सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होने की संभावना है;

(एफ) किसी भी ऐसी वस्तु या वर्ग के वितरण और व्यापार और वाणिज्य में लगे व्यक्तियों से यह अपेक्षा करने के लिए कि वे बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं को बिक्री

मूल्य के साथ चिह्नित करें या परिसर में किसी आसानी से सुलभ स्थान पर मूल्य-सूचियां प्रदर्शित करें। बिक्री के लिए रखे गए सामान और इसी तरह हर महीने के पहले दिन, ऐसे अन्य समय पर, जो निर्धारित किया जा सकता है, स्टॉक में ऐसे किसी भी सामान की कुल मात्रा का विवरण प्रदर्शित करना;

(जी) उपरोक्त किसी भी मामले को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने की दृष्टि से कोई जानकारी या आंकड़े एकत्र करने के लिए; और

(एच) किसी भी आकस्मिक या पूरक मामलों के लिए, जिसमें विशेष रूप से लाइसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेजों का अनुदान या जारी करना और शुल्क वसूलना शामिल है।"

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, धारा 18 जी के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी तक किया जा सकता है जब तक कि उप-धारा (1) द्वारा अनुमति दी गई हो अर्थात् अनुसूचित उद्योग से संबंधित किसी भी वस्तु या किसी से संबंधित वस्तुओं के वर्ग के उचित मूल्य पर समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस सीमा तक राज्य विधानमंडल कोई कानून नहीं बना सकता। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अन्य मामलों में यह क्षेत्र अभी भी राज्य विधानमंडल के लिए खुला है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि विवादित अधिसूचना यह सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है कि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेक्टिफाइड स्पिरिट को देशी शराब या पीने योग्य शराब के अन्य रूपों को प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा जाता है और यह परिशोधित स्पिरिट या डिनेचर्ड स्पिरिट के समान वितरण और उचित मूल्य पर उपलब्धता से संबंधित नहीं है। इस प्रकार, अधिसूचना सूची-॥ सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रविष्टि 6 और सूची-॥ की प्रविष्टि 8- नशीली शराब का कब्जा और बिक्री के तहत उचित थी।

इस न्यायालय ने सिंथेटिक केमिकल्स बनाम यूपी राज्य [(1990) 1 एससीसी 109] = 1989 सप्लिमेंट, (1) एससीआर 623 के मामले में औद्योगिक अल्कोहल पर कर या लेवी लगाने की राज्य की विधायी क्षमता के सवाल पर विचार किया और नकारात्मक फैसला सुनाया। उच्च



न्यायालय ने यह विचार किया कि एथिल अल्कोहल/रेक्टिफाइड स्पिरिट और डिनेचर्ड स्पिरिट के बीच अंतर कोई मुद्दा नहीं था, न ही उस निर्णय में इस पर विचार किया गया था और यह माना गया कि इस न्यायालय ने यह निर्णय नहीं दिया है कि प्रत्येक रेक्टिफाइड स्पिरिट/एथिल अल्कोहल औद्योगिक शराब है. उच्च न्यायालय ने दोहराया कि एक बार विकृत होने के बाद, अल्कोहल विशेष रूप से औद्योगिक अल्कोहल बन जाता है क्योंकि इसका उपयोग देशी शराब प्राप्त करने या आईएमएफएल के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है और कहा कि यह सुनिश्चित करना है कि औद्योगिक उपयोग के लिए बने एथिल अल्कोहल का दुरुपयोग नहीं किया जाए या मानव उपभोग के लिए इसका इस्तेमाल न किया जाए। विवादित विनियमन राज्य द्वारा प्रदान किया गया है और इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में शराब के व्यापार के सामान्य विनियमन का हिस्सा होने के कारण यह विनियमन सूची- II की प्रविष्टि 6 और 8 से संबंधित है

मामले का दूसरा भाग राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और ली गई शुल्क की दर के बीच प्रतिपूर्ति के सवाल से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं के अनुसार लिया गया शुल्क अत्यधिक था और इसलिए बुरा था। उच्च न्यायालय ने नियामक शुल्क और प्रतिपूरक शुल्क के बीच अंतर की ओर इशारा किया। इसने राय दी कि नियामक उद्देश्यों के लिए लगाए गए लाइसेंस शुल्क में प्रदान की गई कोई भी सेवा

शामिल नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा लाइसेंस शुल्क उचित होना चाहिए। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा, विनियमन को प्रशासित करने के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले व्यय पर ध्यान देना उचित होगा और यदि राज्य द्वारा किए गए व्यय और ली गई फीस के बीच व्यापक सह-संबंध है, तो फीस को उचित रूप में बरकरार रखा जा सकता है। इसने यह निष्कर्ष निकालने के लिए राज्य के जवाबी हलफनामे का भी हवाला दिया कि डिस्टिलरी में तैनात कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी प्रयोगशालाओं के प्रबंधन में लगे हुए हैं और इसलिए 7 पैसे प्रति लीटर की दर उचित थी।

इन अपीलों में अपीलकर्ताओं ने दोहराया है कि इस न्यायालय ने सिंथेटिक केमिकल्स (सुप्रा) में अपने 7-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा स्पष्ट रूप से एथिल अल्कोहल/रेक्टिफाइड स्पिरिट के संबंध में राज्य की विधायी क्षमता के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसके अलावा, उनका कहना है कि भले ही राज्य के पास पीने योग्य उद्देश्यों के लिए औद्योगिक शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियामक शक्ति है, लेकिन ऐसी शक्ति में कोई शुल्क लगाने की शक्ति शामिल नहीं है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं का कहना है कि विकृतीकरण यूपी आबकारी अधिनियम के तहत एक अधिसूचना द्वारा लगाया गया एक वैधानिक कर्तव्य है और इसके लिए राज्य द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही है, कोई शुल्क नहीं लिया जा

सकता है और किसी भी मामले में भले ही राज्य को विकृतीकरण की आवश्यकता को लागू करने के लिए कोई खर्च करना पड़े, किए गए खर्चों व लिए गए शुल्क के बीच कोई प्रतिपूर्ति नहीं है।

हमें ऐसा लगता है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में 'औद्योगिक अल्कोहल' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। निर्णय के पहले भाग में उद्धृत सभी प्रविष्टियों को संविधान के अनुच्छेद 248 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो संघ की अवशिष्ट शक्तियों को निर्दिष्ट करता है:

"248. कानून की अवशिष्ट शक्तियां।- (1) संसद के पास समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्ति है।

(2) ऐसी शक्ति में किसी भी सूची में उल्लिखित न किए गए कर को लागू करने वाला कोई भी कानून बनाने की शक्ति शामिल होगी।"

यह सूची-1 की प्रविष्टि 97 में दर्शाया गया है:

"97. कोई भी अन्य मामला जो सूची II या सूची III में शामिल नहीं है, जिसमें उन सूचियों में से किसी भी कर का उल्लेख नहीं है।"

क्या "मादक शराब" के "मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब" के अलावा अन्य अल्कोहलिक शराब राज्य का विषय था या संघ का विषय, यह वास्तविक विवाद होना चाहिए। इस प्रकार की शराब का वर्णन करने के लिए 'औद्योगिक अल्कोहल' शब्द का उपयोग किया जाता है। शराब पर कानून बनाने के लिए केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल को अधिकार क्षेत्र देने वाले कानून के सभी प्रावधानों के विश्लेषण के बाद, सिंथेटिक केमिकल मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने माना कि विक्रेता शुल्क या परिवहन शुल्क आदि के रूप में कुछ शुल्क लगाने वाली अधिसूचनाओं को राज्य की विधायी क्षमता के अंतर्गत माना गया। उस फैसले को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि न्यायालय इस तथ्य से पूरी तरह अवगत था कि रेक्टिफाइड स्पिरिट मानव उपभोग के लिए नशीली शराब या अल्कोहलिक शराब का घटक था, हालांकि रेक्टिफाइड स्पिरिट/एथिल अल्कोहल और साथ ही डिनेचर्ड स्पिरिट को उस फैसले में 'औद्योगिक अल्कोहल' कहा गया है। इस

न्यायालय ने यह नहीं माना कि राज्य के पास "औद्योगिक शराब" के संबंध में कोई भी शक्ति नहीं होगी। दरअसल, फैसले में ही कोर्ट ने औद्योगिक शराब से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन किया है, जिनमें राज्य अभी भी कानून बना सकता है या नियम बना सकता है। फैसले के निम्नलिखित भाग को लाभ के साथ पढ़ा जा सकता है।

"आईडीआर अधिनियम में 1956 के संशोधन के बाद शराब उद्योग के नियंत्रण के संबंध में स्थिति में महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण बदलाव आया है। संशोधन के बाद, राज्य के पास शराब के संबंध में कानून बनाने के लिए केवल निम्नलिखित शक्तियां बची हैं:

(ए) यह सूची II की प्रविष्टि 6 और विनियमन शक्तियों के संदर्भ में पीने योग्य शराब के निषेध की प्रकृति में कोई भी कानून पारित कर सकता है।

(बी) यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकता है कि गैर-पीने योग्य शराब का उपयोग न किया जाए और पीने योग्य शराब के विकल्प के रूप में इसका दुरुपयोग न किया जाए।

(सी) राज्य सूची II की प्रविष्टि 52 के तहत पीने योग्य शराब और बिक्री कर पर उत्पाद शुल्क लगा सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में औद्योगिक अल्कोहल पर बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि एथिल अल्कोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेशों के तहत, राज्य द्वारा औद्योगिक अल्कोहल पर बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है।

(डी) हालाँकि, यदि राज्य तथाकथित विशेषाधिकार अनुदान के दावे से अलग कोई सेवा प्रदान कर रहा है, तो वह बदले में शुल्क ले सकता है। इस संबंध में देखें, इण्डिया

मिका के मामले (सुप्रा) का अवलोकन।" (1989) अनुपूरक

1. एससीआर 623 (681-682)

औद्योगिक उपयोग के लिए स्प्रिट का विकृतीकरण मानव उपभोग के लिए गैर-पीने योग्य अल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए है और जैसा कि न्यायालय ने विशेष रूप से राज्य की विधायी क्षमता के भीतर उल्लेख किया है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि सूची-1 की प्रविष्टि 84 के साथ पढ़ी जाने वाली सूची-2 की प्रविष्टि 8 और 51 के तहत राज्यों को मानव उपभोग के लिए नशीली शराब या मादक शराब पर कानून बनाने का विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है। इसलिए, जब तक किसी भी मादक तैयारी को मानव उपभोग के लिए मोड़ा जा सकता है, राज्यों के पास कानून बनाने के साथ-साथ कर आदि लगाने की शक्ति होगी। इस दृष्टिकोण से, स्प्रिट का विकृतीकरण न केवल राज्यों पर एक दायित्व है, बल्कि लागू करने की राज्यों की क्षमता के भीतर भी है।

श्री बिलेश्वर खान उद्योग खेदुत सहकारी मंडली लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य [1992] 1 एस.सी.आर. 391 के मामले में

आईडीआर अधिनियम के साथ सामना होने पर इस अदालत को तीन सूचियों में समान प्रविष्टियों और उनके प्रभाव से निपटने का अवसर मिला। उस मामले में, चुनौती के तहत मामला औद्योगिक शराब के निर्माण की निगरानी के लिए आबकारी कर्मचारियों के रखरखाव के लिए बॉम्बे निषेध अधिनियम की धारा 58-ए के तहत मांग की वैधता थी, जिस पर राज्य की विधायी क्षमता की कमी का आरोप लगाया गया था। उस मामले में अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि भले ही शराब के उत्पादन की निगरानी करने की राज्य की शक्ति को स्वीकार कर लिया जाए, फिर भी राज्य के पास पर्यवेक्षण की लागत को पूरा करने के लिए कोई लेवी लगाने की शक्ति नहीं है। अदालत ने कहा:

"विद्वान वकील के अनुसार चूंकि उच्च न्यायालय का पूरा फैसला विशेषाधिकार सिद्धांत पर आगे बढ़ा है, इसलिए यह सिंथेटिक और केमिकल के मामले में निर्धारित सिद्धांत का सामना नहीं कर सकता है। सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 8 के तहत शुल्क के रूप में लेवी या प्रविष्टि 51 के तहत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, धारा 58 ए के तहत लगाए गए पर्यवेक्षण की लागत से भिन्न पूर्व को लेवी की कसौटी पर खरा उतरना होगा, जो कि संवैधानिक प्रविष्टियों



में से एक से प्राप्त शक्ति पर कानून के अनुसार है। चूंकि सिंथेटिक और केमिकल का मामला अंततः प्रविष्टि 8 या 51 के दायरे में लाया गया है, किसी भी कर या शुल्क को लगाने के लिए कोई भी कानून बनाने के लिए राज्य की क्षमता को सातवीं अनुसूची की सूची II से बाहर रखा गया है, लेकिन इसके द्वारा राज्य द्वारा पर्यवेक्षण के लिए अधिनियमित एक प्रावधान जो समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत आता है जो उत्पादन से संबंधित है, आपूर्ति और वितरण जिसमें विनियमन शामिल है, पर हमला नहीं किया जा सकता है। सिंथेटिक और केमिकल मामले में खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही औद्योगिक शराब पर कर या शुल्क लगाने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है, फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर-पीने योग्य शराब, यानी, औद्योगिक शराब, नहीं था पीने योग्य शराब के विकल्प के रूप में इसका दुरुपयोग किया गया, राज्य के पास नियम बनाने की शक्ति बची हुई है। यह 58 ए जैसे प्रावधान को सही ठहराने के लिए काफी है। निर्णय के अनुच्छेद 88 में यह देखा गया कि औद्योगिक अल्कोहल के संबंध में राज्यों को शुल्क लगाने के लिए

अधिकृत नहीं किया गया था जैसा कि उन्होंने उस मामले में करने का दावा किया था, लेकिन इससे यह स्थापित करने के लिए परिस्थितियों में शुल्क लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शुल्क के लिए प्रतिपूर्ति थी और न ही यह किसी नियामक उपाय को प्रभावित करेगा। यह अपीलकर्ता की ओर से दिए गए तर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है।"

इस फैसले का अनुसरण बाद के एक मामले में किया गया, जिसमें वही सवाल उठाए गए और बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 58-ए की वैधता को चुनौती दी गई, अर्थात् गुजकेम डिस्टिलर्स इंडिया लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य, 1992. (1) एस.सी.आर. 675। कानूनी स्थिति की उचित विवेचना करने पर, 7 पैसे प्रति लीटर के शुल्क को नियामक उपाय के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए, अर्थात् स्पिरिट का विकृतीकरण और उक्त प्रक्रिया का पर्यवेक्षण।

अभी हाल ही में प्रविष्टि 8 और 24 सूची II की परस्पर क्रिया के प्रभाव से, सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 52 और आईडीआर अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 26 को ए.पी. राज्य और अन्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी एवं अन्य। आदि जेटी 1996 (3) एससी 679

के मामले में माना जाने लगा। आंध्र प्रदेश राज्य ने आंध्र प्रदेश निषेध अधिनियम, 1995 में एक संशोधन द्वारा शराब के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। अधिनियम में 'शराब' को इस प्रकार परिभाषित किया गया था:

"(7). 'शराब' में शामिल है,-

(ए) वाइन, वाइन की स्पिरिट, बीयर और भारतीय शराब और विदेशी शराब सहित अल्कोहल से युक्त या और प्रत्येक तरल से युक्त,

(बी) कोई अन्य नशीला पदार्थ जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शराब घोषित कर सकती है,

लेकिन इसमें टोडी, डिनेचर्ड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट  
और रेक्टिफाइड स्पिरिट शामिल नहीं हैं;"

हम धारा 7 ए पर भी ध्यान दे सकते हैं। उस धारा के द्वारा शराब का  
निर्माण प्रतिबंधित हो गया।

मैसर्स मैकडॉवेल एंड कंपनी, नशीली शराब के निर्माताओं ने  
अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जिसके द्वारा निषेध  
अधिनियम में धारा 7-ए को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया  
था। चुनौती का एक आधार आईडीआर अधिनियम की पहली अनुसूची में  
प्रविष्टि 26 के मद्देनजर विधायी क्षमता की कमी थी, जो रिट  
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, शराब उद्योगों का नियंत्रण विशेष रूप से संघ में  
निहित करता है और राज्य विधानमंडल को शराब के निर्माण को लाइसेंस  
देने या विनियमित करने की शक्ति से वंचित करता है। यह प्रस्तुतिकरण  
इस तथ्य पर आधारित था कि किण्वन उद्योगों को आईडीआर अधिनियम  
की अनुसूची में शामिल किया गया था और इसलिए राज्य को शराब के  
निर्माण को लाइसेंस देने और विनियमित करने की शक्ति से वंचित कर  
दिया गया था। प्रविष्टि 26 में लिखा है "किण्वन उद्योग; (1) अल्कोहल,  
(2) किण्वन उद्योगों के अन्य उत्पाद"। यह तर्क दिया गया कि संशोधन के

बाद ऐसे उद्योगों और उनके उत्पाद का नियंत्रण और विनियमन संघ के विशिष्ट प्रांत के अंतर्गत आ गया और इसलिए राज्य ने लाइसेंस देने, अस्वीकार करने या नवीनीकृत करने की अपनी क्षमता खो दी। कानून के सभी प्रासंगिक प्रावधानों के विश्लेषण के बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:

"हमें पहले सूची II में प्रविष्टि 24 और प्रविष्टि 8 के संबंधित क्षेत्रों को तैयार करना होगा। प्रविष्टि 24 उद्योगों से संबंधित एक सामान्य प्रविष्टि है जबकि प्रविष्टि 8 अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन और निर्माण में लगे उद्योगों से संबंधित एक विशिष्ट और विशेष प्रविष्टि है। ऐसी स्थिति (विशेष सामान्य को छोड़कर) पर लागू व्याख्या के प्रसिद्ध नियम को लागू करते हुए हमें यह मानना चाहिए कि नशीली शराब के उत्पादन और निर्माण में लगे उद्योग प्रविष्टि 24 के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन प्रविष्टि 8 के अंतर्गत आते हैं। संविधान के प्रारंभ में यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति है। एक बार ऐसा हो जाने पर, सूची I की प्रविष्टि 52 के अनुसार संसद द्वारा घोषणा करने पर स्थानांतरण या स्थानांतरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि कहा जा सकता है, राज्य सूची से लेकर संघ सूची तक

नशीली शराब के उत्पादन और निर्माण में लगे उद्योग वास्तव में संसद नशीली शराब के उत्पादन और निर्माण में लगे उद्योगों का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले सकती है। सूची-1 की प्रविष्टि 52 के तहत एक घोषणा करके शराब का निर्माण क्योंकि उक्त प्रविष्टि केवल सूची II में प्रविष्टि 24 को नियंत्रित करती है, लेकिन सूची II में प्रविष्टि 8 को नहीं।"

फैसले के बाद के भाग में इसे इस प्रकार दोहराया गया:

"उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि विनिर्माण और उत्पादन और इसके निषेध (सूची-II में प्रविष्टि 8 में उल्लिखित अन्य मामलों के साथ) के संबंध में कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों के पास है। पहली अनुसूची में आइटम 26 आई.डी.आर. अधिनियम को सूची-II में प्रविष्टि 8 -और उस मामले के लिए, प्रविष्टि 6 -के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। तो पढ़ें, उक्त वस्तु नशीली शराब के निर्माण, उत्पादन से संबंधित नहीं है और न ही हो सकती है। हमारे समक्ष सभी याचिकाकर्ता नशीली शराब के

निर्माण में लगे हुए हैं। इसलिए, राज्य विधानमंडल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-11 में प्रविष्टि 8 और 6 अनुच्छेद 47 के साथ पठित के संदर्भ में - उनकी बिक्री, खपत, कब्जे और परिवहन के अलावा उनके निर्माण और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में लाइसेंस के लिए ली जाने वाली फीस, यानी नियामक शुल्क और प्रतिपूर्ति शुल्क के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के शुल्क के बीच अंतर किया है। उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए भेद को अनुच्छेद 110 के खंड (2) में देखा जा सकता है:

"110.(2) - किसी विधेयक को केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि इसमें जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने, या लाइसेंस के लिए शुल्क की मांग या भुगतान या प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क का प्रावधान है, या उन कारणों से कि यह स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा किसी भी

कर को लगाने, समाप्त करने, छूट देने, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है।"

उच्च न्यायालय ने कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता बनाम लिबर्टी सिनेमा, एआईआर 1965 एससी 1107 = [1965] 2 एस.सी.आर. 477 मामले में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है, जो शेनन बनाम लोअर मेनलैंड डेयरी प्रोडक्ट्स बोर्ड, (1938) एससी 708 = एआईआर (1939) पीसी 36 में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर आधारित था। इस न्यायालय ने कलकत्ता निगम बनाम लिबर्टी सिनेमा (सुप्रा) में कहा था:

"वास्तव में, हमारे संविधान में लाइसेंस के लिए शुल्क और प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्कको विभिन्न प्रकार के लेवी के रूप में माना गया है। पूर्व का उद्देश्य प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क नहीं है। यह अनुच्छेद 110(2) और अनुच्छेद 199(2) के विचार से स्पष्ट है जहां दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग यह दर्शाता है कि वे समान नहीं हैं।"



उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि नियामक शुल्क के मामले में, लाइसेंस शुल्क की तरह, प्रतिपूर्ति का अस्तित्व आवश्यक नहीं है, हालांकि लगाया गया शुल्क, मामले की परिस्थितियों में, अत्यधिक नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि विकृतीकरण की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण में शामिल कार्य की मात्रा और प्रकृति और राज्य द्वारा किए गए परिणामी खर्चों को ध्यान में रखते हुए, 7 पैसे प्रति लीटर का शुल्क उचित और उचित था। हमें उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलें खारिज की जाती हैं। कोई लागत नहीं.

बी.के.एस

अपीलें खारिज की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वर्षा आमोरा (आर. जे. एच. एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारीक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।